

घाटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान के भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक लगाई रोक....

मुंबई, 27 अक्टूबर 2026। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म अभिनेता इमरान खान को फॉरनर्स रोजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी। अमेरिकी नागरिक खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। फिल्म अभिनेता इमरान खान को दी गई भारत छोड़ने की नोटिस को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र विपारी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष सुनवाई हो रही थी। खान की ओर से पेश वकील वेंकटेश थोंड ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।



इसके साथ ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को आशवासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने इमरान खान पर कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देते हुए मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था।

मध्यप्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की दिनचर्या बदली, तीन आरतियों का नया समय लागू

उज्जैन, 27 अक्टूबर 2026। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से बाबा महाकाल की दिनचर्या बदली गई है। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली तीन आरतियों के समय में शीतकाल के अनुसार बदलाव किया गया है। मंगलवार को सुबह की दशोदक (बालभोग) और भोग आरती आधा घंटा देरी से हुई। मंदिर के पुजारी पं. महेश शर्मा ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की पूजा परंपरा में मौसम के अनुसार बदलाव किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान की पूजन परंपरा में शरद पूर्णिमा से सर्दी की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन संख्या आरती में भगवान महाकाल को केसरिया मोटे दूध का भोग लगा गया। इसके बाद अगले दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से मंदिर में प्रतिदिन होने वाली पांच आरतियों में से तीन आरतियों का समय बदलता है। प्रतिदिन सुबह की दशोदक (बालभोग) और भोग आरती अब आधा घंटा देरी से होंगी, जबकि संख्या आरती आधा घंटा पहले की जाएगी। यह व्यवस्था फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली तक जारी रहेगी।



दिल्ली में राहुल गांधी की जन सुनवाई...कहा- सीईसी के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा विपक्ष, ऊपर से हो रही वोट चोरी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित ब्लॉक 20 में 'वोट अधिकार जीने का अधिकार' जन सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि देश में ऊपर के स्तर से वोट चोरी की जा रही है और गरीबों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा, "इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। वोट भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद देशभर में करोड़ों लोगों से उनका यह अधिकार



चार बूथों से 416 नाम हटाने का आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि इस जन सुनवाई के जरिए लोगों ने बताया कि चार बूथों से 416 नाम कथित तौर पर अवैध तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा, "भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हम लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज लोगों को समझ आ गया है कि वोट चोरी हो रही है और गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।"

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की बात

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष उनसे सवाल करता है, तो उन्हें जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा, "जब हम ज्ञानेश कुमार से सवाल करते हैं, तो वह जवाब नहीं देते। विपक्ष तब तक नहीं रुकेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते।"

यानी वोट व्यवस्थित तरीके से छीना जा रहा है।" गरीबों के नाम जानबूझकर हटाने का आरोप : राहुल गांधी ने आगे कहा, "हम लंबे समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझने लगा है कि ऊपर के स्तर से वोट चोरी हो रही है।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गरीबों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे उनके अधिकार और सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, "गरीबों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और उनके अधिकार तथा सुविधाएं छीनी जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक ऐसा नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, जो कुछ चुने हुए अरबपतियों को हो। जहां आम नागरिकों और गरीबों के अधिकार न हों और देश केवल अरबपतियों के हित में चलाया जाए।"

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की याचिका पर केंद्र को नोटिस

21 मीडिया ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा... डेटा प्रोटेक्शन कानून से खबरों की रिपोर्टिंग करना मुश्किल होगा

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। यह याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कानून में पत्रकारिता को छूट नहीं मिलने से खोजी पत्रकारिता, खबरों की रिपोर्टिंग और गोपनीय स्रोतों की पहचान सुरक्षित रखने में मुश्किल हो सकती है। न्यूज पब्लिशर्स ने कानून के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। एसोसिएशन ने डेटा कानून के तहत निजी जानकारी के इस्तेमाल के लिए सहमति की शर्त, आर्टिआई कानून में बदलाव और सरकार को दी गई जानकारी मांगने की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।



डेटा कानून को चुनौती देने वालों में अंबानी-अडानी की भी कंपनियां : डीएनपीए ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें डेटा प्रोटेक्शन कानून और उससे जुड़े नियमों के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन में देश के 21 न्यूज पब्लिशर्स शामिल हैं। इनमें मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाला नेटवर्क 18, गौतम अडानी का एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया समूह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल माध्यमों पर लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया है। इसके तहत डिजिटल पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करने वाले संगठनों पर नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी तय की गई है। न्यूज पब्लिशर्स का कहना है कि मीडिया संस्थानों को छूट नहीं मिलने से प्रेस की आजादी प्रभावित हो सकती है। याचिका में कानून के विवादित प्रावधानों को रद्द करने के साथ सुनवाई के दौरान उन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है।

भारत में इनोवेशन की परंपरा रही...शून्य की खोज की, नंबर सिस्टम बनाया, हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। हमें आज जो सफलताएं मिल रही हैं, वे पहले कभी नहीं मिलीं। 'विकसित भारत' की नींव वैज्ञानिक अनुसंधान पर टिकी होगी। भारत एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य नई तकनीकें विकसित करना है। हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना है। ये बातें पीएम मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडप में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के उद्घाटन में कहीं। ESTIC साइंस-इनोवेशन से जुड़ा एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह 27-28 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें 12 सेक्टरों पर चर्चा की जाएगी। तीन नोबेल विजेता इसके स्पीकर होंगे। इस साल की थीम है-रचनात्मक सोच से विज्ञान को गति देना और तकनीक को सशक्त बनाना। कार्यक्रम का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कर रही है।

लगभग तैरसे ड्रॉट में पीएम का नारा-ची विल इ डट

पीएम मोदी ने कहा... हमें अपने वैज्ञानिकों और संस्थानों को आज की जरूरतों के साथ भविष्य के लिए भी तैयार करना है। एआई, स्पेस और सेमीकंडक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो फ्यूचर को शेप और सेफ करेंगे। इसलिए नई-नई कोशिशों की जा रही है। इस दौर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी नई परेशानियां आ रही हैं। हमारा लक्ष्य ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना है जो देश को आगे बढ़ाए। इस कॉन्क्लेव में मौजूद सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो एक लक्ष्य लें कि वह कौन सा टैलेंट विकसित करेंगे जिससे दुनिया को फायदा हो। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास प्रतिभा और कुछ नया करने का संकल्प है। हमारा भाव हो वो विल इ डट, हमारा संकल्प हो वो विल इ डट।

एआई के दौर में साइंटिफिक टेम्पामेंट विकसित करना जरूरी

पीएम ने कहा... सरकार की ओर से 12 हजार करोड़ के कमिटमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर भी 12 हजार करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। भारत के रिसर्च इकोसिस्टम में भी निरंतर विस्तार दिख रहा है। 10 साल पहले साल में 50 हजार से कम पेटेंट दाखिल होते थे। लेकिन पिछले साल ये संख्या 1.5 लाख पहुंच गई। 21वीं सदी के इस दूसरे क्वार्टर में ये बहुत जरूरी हो गया है कि इस एआई के दौर में साइंटिफिक टेम्पामेंट कैसे विकसित होगा। वह उन पहलुओं को पहचानता है जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं गया। लेकिन आज एआई के दौर में हमारे पास चुनौती भी है। एआई के दौर में रूटीन काम कर सकता है। लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे साइंटिफिक टेम्पामेंट पर कोई असर न हो।

रिसर्च वह शक्ति, जो किसी देश को समस्याओं को समझने में मददगार

पीएम ने कहा... कुछ दिन पहले ही मुझे चेन्नई जाने का मौका मिला। वहां मैंने आईआईटी मद्रास में एक आधुनिक ब्रेन सेंटर का उद्घाटन किया। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जहां दिमाग की 3डी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इससे दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा। हम सब जानते हैं रिसर्च वो शक्ति है जो किसी देश को अपनी समस्याओं को समझने में मदद करती है। इसलिए हमने कहा है जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसलिए हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले साल हमने इसी मंच से इसके लिए 1 लाख करोड़ दिया था।

भारत-विली एफटीए अंतिम चरण में, कनाडा से वार्ता में अच्छी प्रगति : गोयल

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। नीदरलैंड की यात्रा पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कई देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि चिली के साथ वह वार्ता समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब है, जबकि कनाडा के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। गोयल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे लगता है कि चिली के साथ चल रही मौजूदा बातचीत समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब है। कनाडा के साथ बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने एसएससीयू के साथ बातचीत अभी शुरू की है, इसलिए इसे पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व वाले दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ बातचीत शुरू हो गई है।



हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे जो हेल्थ और एजुकेशन में काम आए...

आप सब जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को हमेशा से वेपन की तरह भी देखा जाता रहा है। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब है आम जनता की सेवा। टेक्नोलॉजी सिर्फ इस बात से साबित नहीं होती कि वो कितनी एडवांस है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाती है। इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो हेल्थ और एजुकेशन में काम आए।

भारत में बने शिपमेंट अब दुनिया में पहुंच रहे हैं...

मोदी ने कहा... इसी साल भारत ने एआई इंपैक्ट समिट होस्ट की और अपना भी लॉन्च तैयार किया। भारत में तैयार शिपमेंट अब दुनिया में पहुंच रहे हैं। न्यूक्लियर से स्पेस और एआई से सेमीकंडक्टर तक इन सबकी जरूरतें अलग हैं। लेकिन लक्ष्य एक है। भारत का एक और लक्ष्य है-सॉल्यूशन एट स्केल, यानी हमारे यहां बूढ़े हुए सॉल्यूशन से दुनिया को फायदा होता है।

इंडियन स्टार्टअप ने पहली कोशिश में रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचाया

प्रधानमंत्री ने कहा... 30 अक्टूबर को देश डॉक्टर होमी भाभा की जयंती मनाएगा। आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत के लिए हमें बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर पनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए हम अपने फास्ट ब्रीड रिप्लेयर तैयार कर रहे हैं। ये कुछ महीने पहले ही फर्स्ट क्लिकलेटि तक पहुंच गया है। इसी साल भारत ने स्पेस सेक्टर में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मेड इन इंडिया स्टार्टअप ने पहली कोशिश में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया। 21वीं सदी का भारत एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हमारा लक्ष्य नई तकनीकें बनाना, उनकी दिशा तय करना और वैश्विक चुनौतियों के समाधान देने की क्षमता विकसित करना है। पीएम ने कहा... आज हमारे सामने चुनौती है- नई टेक्नोलॉजी विकसित करना है। हमने कोरोना काल में देखा जब दुनिया के बड़े देश वैक्सीन के लिए स्टगल कर रहे थे। तब भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दी। हम प्रथम कोशिश में ही मंगल पर पहुंच गए। हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक भी एक बार में ही पहुंच गए। 0 की खोज से लेकर नंबर सिस्टम तक भारत की परंपरा इनोवेशन की रही है।

ब्रिक्स संसदीय मंच में सीमापार आतंकवाद की निंदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच मंगलवार को संयुक्त घोषणा-पत्र अंगीकृत किए जाने के साथ संपन्न हो गया। घोषणापत्र में सीमापार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने की निंदा करते हुए इसके खिलाफ शून्य सहिष्णुता अपनाने और दोहरे मापदंडों से बचने की अपील की गई। साथ ही, वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों का समर्थन किया गया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभु समानता, परस्पर सम्मान, देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसमें नई दिल्ली घोषणा-पत्र में व्यक्त सहमतियों को भी दोहराया गया। घोषणा-पत्र में वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन किया गया। इसमें कहा गया कि वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में विकासशील देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत पर बल देते हुए सीमापार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और



आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने की निंदा की गई। घोषणा-पत्र में आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड नहीं अपनाने का भी आह्वान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि वैश्विक चुनौतियों का स्थायी समाधान संघर्ष के बजाय संवाद, युद्ध के बजाय शांति और प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग में निहित है। उन्होंने राष्ट्रीय संघभुता के सम्मान, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के लिए समान विकास अवसरों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के पीठसीन अधिकारियों तथा सांसदों के संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सदस्य देशों की पृष्ठभूमि और चुनौतियां अलग-अलग होने के बावजूद मानवता के कल्याण, शांति और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता इस समूह की ताकत है।

सुप्रीम कोर्ट बोला...पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद कर रहा

एचआरपी और रिटेलर कोमनों में अंतर, मरतल वगैरह का 10% खर्च दवाओं पर

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत और रिटेलर को मिलने वाली कीमतों में भारी अंतर पर सरकार से सवाल किए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद क्यों कर रहा है। कोर्ट ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को निष्क्रिय बताते हुए सवाल किया कि दवाओं की कीमतों पर लामबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नजरों

के सामने यह सवाल हो रहा है, क्या इसे ऐसे ही बेलगाम चलने देना चाहिए। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुद्दा ये है कि कई दवाओं की लागत 10-20 रुपये है, यह रिटेलर को 30 रुपये में मिलती है, पर एमआरपी 150-200 रुपये छया होता है। यही गैप कोर्ट को खटक रहा है।



योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी...चार औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, कई अहम फैसलों पर मुहर

नोएडा, 27 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए। किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े प्रस्तावों को विशेष प्राथमिकता दी गई। ये निर्णय प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होंगे। कैबिनेट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति रखता है। हलालीक, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है।

औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति : यूपी कैबिनेट ने नोएडा गौतमबुद्ध



नगर की चार औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर ऑफ फंक्ट जारी करने की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1709.84 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। हैबेल्स इंडिया लिमिटेड 879 करोड़ रुपये और एलजी सॉफ्ट 634 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी 112.84 करोड़

रुपये तथा मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 84 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इनमें से दो परियोजनाएं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। शेष दो परियोजनाएं निजी भूमि पर स्थापित की जाएंगी। इन निवेश प्रस्तावों से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर : सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के तहत रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। उद्यमिता विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सड़क व बुनियादी ढांचे पर 100 रुपये खर्च से अर्थव्यवस्था पर 325 रुपये का प्रभाव : गडकरी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्च का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इंफ्रस्ट्रक्चर पर 100 रुपये खर्च करने से अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद पर 325 रुपये के बराबर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे, पर्याप्त बिजली और पानी के बिना कृषि, उद्योग, व्यापार और निवेश को

बढ़ावा देना संभव नहीं है। गडकरी मंगलवार को यहां भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के राष्ट्रीय सम्मेलन 'हाईवेज ऑफ इंडियाज फ्यूचर : स्मार्ट, सेफ एंड सेक्टरनेबल' में शामिल हुए। उन्होंने सड़क निर्माण, आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक्स लागत, निर्माण की गुणवत्ता और वैकल्पिक ईंधन से जुड़ी योजनाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए



लॉजिस्टिक्स लागत घटाना जरूरी है। दो वर्ष पहले चीन में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की करीब आठ फीसदी थी, जबकि भारत में

यह 16 फीसदी थी। इस अंतर को कम करने के लिए देश में ग्रीन एक्सप्रेसवे और दो से छह लेन तक की सड़कों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2014 से 2026 के बीच बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई। चार लेन और उससे अधिक चौड़ी सड़कों की लंबाई 18,278 किलोमीटर से बढ़कर

49,260 किलोमीटर पहुंच गई है। हाई-स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क भी 557 किलोमीटर से बढ़कर 6,788 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 22 हजार करोड़ रुपये की लागत से रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग सुरु बनाई जा रही है। अगले पांच से सात वर्षों में जलविद्युत, मेट्रो और राजमार्गों से जुड़ी सात से आठ लाख करोड़ रुपये की सुर्ग परियोजनाएं विकसित होने की संभावना है।

वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस,पांच नाबालिग पकड़ाए

नमनाकला पॉलिटेक्निक ग्राउंड में छात्र से मारपीट का मामला...बुलेट जब्त,लेकिन सवाल यह कि ऐसी घटनाओं पर पहले से अंकुश क्यों नहीं?

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

शहर में मामूली विवाद पर मारपीट, सरेआम दबंगई और घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमनाकला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में दसवीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट के मामले में गांधीनगर पुलिस ने पांच विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ने और घटना में प्रयुक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त करने की जानकारी दी है। पुलिस की कार्रवाई को मामले में प्रगति जरूर माना जा सकता है,लेकिन इस घटना ने शहर में किशोरों की सुरक्षा,कानून के प्रति सम्मान और पुलिस की निवारक कार्रवाई को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकरण के अनुसार,छात्र अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान बुलेट मोटरसाइकिल चलाने की बात को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने गाली-गलौज करते हुए छात्र को नमनाकला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड की ओर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। उसे बचाने पहुंचे साथी के साथ भी मारपीट किए जाने की शिकायत है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाने में अपराध क्रमांक 679/26 के तहत भारतीय न्याय सहिता



वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई,पहले की सतर्कता कहां थी?

इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि एक छात्र के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। सवाल यह नहीं कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा क्यों, बल्कि सवाल यह है कि शहर के संवेदनशील इलाकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से कितनी प्रभावी निगरानी और गश्त हो रही है। 24 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों में बताया गया था कि छात्र को कथित रूप से जब्तन पॉलिटेक्निक ग्राउंड ले जाकर पीटा गया और घटना का वीडियो वायरल हुआ। शुरुआती रिपोर्टों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की जानकारी थी। अब पांच बालकों को पकड़े जाने की पुलिस की सूचना सामने आई है। इससे कार्रवाई में प्रगति स्पष्ट है,लेकिन यह भी सामने आता है कि घटना के बाद जांच और आरोपियों की पहचान का काम महत्वपूर्ण रहा। यहां पुलिस की भूमिका केवल अपराध दर्ज करने और घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती। सार्वजनिक स्थानों, स्कूल-कॉलेज के आसपास और उन इलाकों में जहां तेज रफ्तार वाहन चलाने तथा विवाद की शिकायतें सामने आती हैं, नियमित निगरानी और त्वरित हस्तक्षेप भी जरूरी है।

अंबिकापुर में पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी घटनाएं...
 यह मामला किसी एक घटना को शहर की पूरी कानून-व्यवस्था का प्रमाण मानने का आधार नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में सामने आए दूसरे प्रकरणों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। फरवरी 2026 में महामाया चौक के पास नगर सैनिक और युवकों के बीच विवाद तथा मारपीट का वीडियो सामने आया था। अप्रैल 2026 में अंबिकापुर के एक पटवारी कार्यालय में मारपीट की घटना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगस्त में वाटर पार्क में दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो प्रसारित होने की खबर आई। इन घटनाओं की परिस्थितियां अलग-अलग थीं,लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर विवाद के हिंसा में बदलने और वीडियो के माध्यम से मामला व्यापक चर्चा में आने का पहलू सामने आया। दिसंबर 2025 में घटती-घटना ने मणिपुर थाना क्षेत्र के दरीपारा में दो युवकों की पिटाई के मामले में भाजपा पार्थद के बेटे सहित छह आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर भी प्रकाशित की थी। इन घटनाओं से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि हर मामले में पुलिस निष्क्रिय रही, लेकिन इतना जरूर है कि मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए केवल बाद की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। रोकथाम,निगरानी और अपराध के प्रति स्पष्ट संदेश भी उतारने ही जरूरी है।

की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई करते हुए पांच विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।
नाबालिग होना राहत नहीं, सुधार की जिम्मेदारी भी जरूरी : इस प्रकरण में पकड़े गए पांचों को पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक बताया है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई के साथ किशोर न्याय व्यवस्था के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नाबालिग होने का अर्थ यह

नहीं कि हिंसा को सामान्य या स्वीकार्य मान लिया जाए। वहीं, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि बालकों को सुधार और पुनर्वास का अवसर देना भी है।
 परिवार,स्कूल, समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किशोरों में बढ़ती आक्रामकता, समूह के दबाव और दूसरों को डराने की प्रवृत्ति को समय रहते पहचाना जाए। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो बनाना या उसे प्रसारित करना किसी घटना को सामने लाने में मददगार हो सकता है,लेकिन हिंसा को मनोरंजन या बहलुरी के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना समस्या को और गंभीर बना सकता है।

भागवत कथा का श्रवण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है,यही भागवत की पूर्णता है सातदिवसीय भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आज हुआ समापन

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

ओंकारेश्वर शिव मंदिर राजेंद्र नगर में चल रहे सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आज मंगलवार को समापन हुआ। अंतिम दिन व्यास पीठ पर विराजे ललित नरेंद्र जी महाराज ने भागवत कथा सार बताया। साथ ही नव योगेश्वर कथा, कृष्ण-सुदामा मित्रता, एवं परीक्षित मोक्ष की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा उपरांत तुलसीवर्षा,गीता दान,और पूर्णाहुति उपरांत भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिव मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा के आखिरी दिन कथा व्यास पीठ पर विराजे ललित नरेंद्र जी महाराज ने कहा कि जीव व आत्मा के कल्याण हेतु प्रभु ने जो उपदेश दिया वह भागवत है। मनुष्य को अपने अपराध का बोध कर देना ही भागवत का सार है। भागवत कथा का श्रवण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है यही भागवत की पूर्णता है। सुदामा चरित्र का सुंदर व्याख्यान करते हुए ललित नरेंद्र जी महाराज ने बताया कि जीवन में मित्रता की शिक्षा कृष्ण और सुदामा से लेना चाहिए। सुदामा अपने कर्मां से गरीब ब्राह्मण बन गए। पत्नी के बार-बार आग्रह पर सुदामा अपने बालसखा कृष्ण से मिलने उनके राज महल पहुंचे तब भूखे व्यासे जीर्ण शीर्ण अवस्था में वे दरवाजे पर ही बैठ गए कि बिना मिले नहीं जाऊंगा।तब द्वारपाल ने जाकर कृष्ण को बताया की है राजन बाहर एक भिखारी आया है वह अपना नाम सुदामा बता रहा है, इतना सुनते ही भगवान समझ गए और बेतहाशा दौड़ पड़े। जा कर



सुदामा को गले से लगा लिया। सम्मानपूर्वक अपने राज सिंहासन पर बैठाया एवं कुशल क्षेम पूछने लगे। स्वयं भगवान जमीन पर बैठे और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। पंडित ललित नरेंद्र जी महाराज ने अपने मधुर आवाज में भजन 'देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोये,पानी परात का छुए नहीं बस नैनन जल से पग धोए' गाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कृष्ण ने सुदामा के दो मुट्ठी चावल ग्रहण किया और दरिद्र सुदामा का जीवन सुखमय बना दिया। पंडित ललित नरेंद्र जी महाराज ने मार्मिक अंदाज में कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कथा उपरांत भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में शिव मंदिर सेवा समिति के एम के नामदेव,कृष्णमुरारी श्रीवास्तव,रमेश केडिया, लक्ष्मीप्रसाद मिश्रा,सौरभ बाजपेई,संजय शर्मा,नीरज नामदेव,रमेश सिंह, शिवजी पांडे, चौरेंद्र श्रीवास्तव,बिन् भास्कर,गोपाल जो पांडे का सक्रिय सहयोग रहा।

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

खेतों में पककर तैयार हो रही धान की फसल पर अब मौसम की मार का खतरा मंडराने लगा है। रायपुर मौसम केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 के बीच सरगुजा जिले में बारिश, गरज-चमक,आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 15 से 70 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। विशेष रूप से 30 अक्टूबर को करीब 70 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। ऐसे में खेतों में खड़ी धान की फसल गिरने और कटाई के बाद खुले में रखी उपज भीगने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। धान की फसल किसानों की सालभर की मेहनत और आमदनी का प्रमुख आधार है। ऐसे समय में लगातार बारिश होने से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ कटाई और मड़ाई का काम भी बाधित हो सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने पर पककर तैयार धान के खेतों में गिरने की आशंका रहती है। वहीं, खुले में रखी कटी फसल और अनाज की बोřियां भीगने से उपज को सुखाने,भंडारण और बिक्री में परेशानी बढ़ सकती है।



कटाई-मड़ाई रोकने और उपज ढककर रखने की सलाह

कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉ. रंजीत कुमार एवं यमलेश निषाद ने किसानों को प्रतिकूल मौसम के दौरान धान की कटाई, मड़ाई और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कृषि कार्य स्थगित रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कटी हुई धान की फसल तथा अनाज को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। खेतों या खलिहानों में रखी फसल के ढेर तथा अनाज की बोřियों को तिरपाल से अच्छी तरह ढकें,ताकि बारिश का पानी उपज को नुकसान न पहुंचा सके। खेतों में जलभराव से बचने के लिए निकासी नालियों को साफ रखना भी जरूरी है। भारी बारिश के कारण सब्जियों और दलहन की फसलों में पानी भरने तथा फलदार पौधों की शाखाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इसलिए किसान अपने खेतों की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत के अनुसार जल निकासी की व्यवस्था करें।

बिजली गिरने के खतरे को भी नजरअंदाज न करें : जोनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन, अंबिकापुर के सहायक

संचालक अनुसंधान डॉ. के.एल. पैकरा ने किसानों से मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की

अंबिकापुर से पहली उड़ान में रायपुर रवाना हुए टीएस सिंहदेव एलायंस एयर की नई हवाई सेवा का शुभारंभ,बोले...सरगुजा के लिए लंबे प्रयासों का सुखद परिणाम... 2,100 में किया सफर

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद अंबिकापुर से रायपुर के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई। मंगलवार, 27 अक्टूबर को मां महामाया विमानतल से एलायंस एयर की नई उड़ान सेवा के जरिए छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव रायपुर के लिए रवाना हुए। क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई विमान सेवा की शुरुआत को लेकर सिंहदेव ने खुशी जताई थी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को धरातल पर उतारने के लिए सामूहिक प्रयास किए गए,जिनका परिणाम अब सामने आया है। उन्होंने बताया था कि उन्हें इस पहल के तहत टिकट उपलब्ध कराया गया और उन्होंने 2,100 में रायपुर की यात्रा करने की बात कही। सिंहदेव ने यह भी कहा कि वे आगे भी इस हवाई सेवा का लाभ लेते रहेंगे।

सड़क की लंबी यात्रा से मिलेगी राहत : अंबिकापुर से रायपुर जाने वाले यात्रियों को अब सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करने के अलावा हवाई यात्रा का विकल्प भी उपलब्ध हो गया है। निर्धारित



समय-सारणी के अनुसार,अंबिकापुर से रायपुर की उड़ान दोपहर 2:05 बजे रवाना होकर लगभग 3:05 बजे रायपुर पहुंचने के लिए निर्धारित है। इस सेवा को अंबिकापुर की उड़ान दोपहर 12:40 बजे रवाना होकर लगभग 1:40 बजे मां महामाया विमानतल पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। इस सेवा का संचालन 72 सीटों वाले एटीआर विमान से किया जाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार,अंबिकापुर और रायपुर के बीच उड़ान मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान

की तारीख और समय की पुष्टि करने की सलाह दी गई है।
रायपुर के आगे भी हवाई सफर होगा आसान : इस नई सेवा का महत्व केवल अंबिकापुर और रायपुर के बीच यात्रा तक सीमित नहीं है। रायपुर से देश के अन्य शहरों के लिए उपलब्ध कनेक्टिंग उड़ानों के जरिए सरगुजा के यात्रियों को आगे की यात्रा में भी सुविधा मिल सकती है। हालांकि,एक ही दिन में दूसरे शहर तक पहुंचना संबंधित उड़ान के समय,कनेक्शन और टिकट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। नई हवाई सेवा से व्यापार,पर्यटन,चिकित्सा और प्रशासनिक कार्यों के लिए राजधानी आने-जाने वाले

लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरगुजा संभाग की राजधानी से संपर्क व्यवस्था मजबूत होने के साथ क्षेत्रीय आवागमन के नए विकल्प भी खुलेंगे।

लंबे समय से थी हवाई कनेक्टिविटी की मांग : सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यहां से रायपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में पर्याप्त समय लगता है। ऐसे में अंबिकापुर से सीधी विमान सेवा शुरू होना स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और जरूरी कार्यों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एलायंस एयर की इस पहल से क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार हुआ है। अब इस सुविधा की वास्तविक उपयोगिता नियमित संचालन, समयबद्ध उड़ानों,उचित किराये और पर्याप्त यात्री संख्या पर निर्भर करेगी।

सरगुजा के लिए उम्मीदों की उड़ान

अंबिकापुर से रायपुर की विमान सेवा शुरू होना क्षेत्र की परिवहन सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब जरूरत इस बात की है कि सेवा निर्यात बनी रहे और यात्रियों को टिकट,समय-सारणी तथा कनेक्टिंग उड़ानों की पर्याप्त जानकारी मिलती रहे,ताकि सरगुजा के लोगों को इस सुविधा का वास्तविक लाभ मिल सके।

पीजी कॉलेज के 50 विद्यार्थियों ने साइबर सेल में लिया प्रशिक्षण

एआई आधारित निगरानी प्रणाली,ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों की जांच की प्रक्रिया समझी



—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत साइबर सेल अंबिकापुर का शैक्षणिक भ्रमण कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराधों की जांच, ऑनलाइन ठगी से बचाव और पुलिस की तकनीकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा की अनुमति तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा और विभागाध्यक्ष मोनिका खेस के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का विषय 'Cyber Security Awareness: On-Field E&perience of Digital Security and Law at Cyber Cell Ambikapur' था। कार्यक्रम का समन्वय सहायक प्राध्यापक उमेश पांडेय, विनोद कुमार गुप्ता और अनुभव श्रीवास्तव ने किया। साइबर विशेषज्ञ गणेश कदम ने विद्यार्थियों को शहर की निगरानी व्यवस्था, कैमरा प्रणाली, फेंस डिटेक्शन, वाहन सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने साइबर सेल में उपयोग किए जा रहे

तकनीकी उपकरणों का प्रदर्शन भी किया और विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। कंट्रोल रूम में डायल 112 के अधिकारियों ने आपातकालीन सहायता,यातायात नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं,उपनिरीक्षक अभय तिवारी ने केस स्टडी के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, मोबाइल गुप्त होने,साइबर ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के बारे में बताया। उन्होंने साइबर अपराध का शिकार होने पर समय पर शिकायत दर्ज कराने और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की महता भी समझाई। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930, आपातकालीन सेवा 112 तथा सीईआईआर सहित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। कंप्यूटर साइंस विभाग के बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों के लिए यह भ्रमण किताबी ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने का अवसर रहा। इससे पहले भी विभाग के विद्यार्थियों ने अंबिकापुर पॉलीटेक्निक कॉलेज में एआईसीटीईट्ट द्वारा आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम में स्टेट फॉरेंसिक टीम, इसरो के वैज्ञानिकों और साइबर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

—संवाददाता—
 उदयपुर, 27 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

ग्राम बासेन के हरीघाट में हाथियों के आतंक से बेघर हुए बुजुर्ग दंपती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दो दिन पहले हाथियों ने उनका कच्चा मकान तोड़ दिया था। इसके बाद दंपती टूटे घर के बाहर पेड़ के नीचे

रात गुजार रहा था। इसी दौरान हाथियों के पहुंचने पर मची अफरा-तफरी में एक हाथी ने बुजुर्ग महिला को लात मार दी। हृदय में करीब 60 वर्षीय नंदकुंवर की कमर में गंभीर चोट आई है। उन्हें रात करीब डेढ़ बजे उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, रात में



जंगल किनारे पेड़ के नीचे बैठे दंपती को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद हाथी वहां पहुंच गए। इसी दौरान भागते

हुए एक हाथी ने नंदकुंवर को लात मार दी। चोट इतनी गंभीर थी कि महिला करवट भी नहीं ले पा रही थी। सूचना मिलने पर क्षेत्र में 11 हाथियों की निगरानी कर रहा वन अमला मौके पर पहुंचा और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। हरीघाट जंगल के करीब एक किलोमीटर के दायरे में पांच से

आठ कच्चे मकान बने हुए हैं। वन अमले ने इन घरों में रहने वाले लोगों को शाम 5 से 6 बजे तक जंगल से दूर सुरक्षित बस्ती में पहुंचने की समझाशा दी है। हालांकि,कुछ ग्रामीण घर में रखे अनाज और अन्य सामान को बचाने के लिए वहां से जाने को तैयार नहीं हैं।

17वें वार्षिकोत्सव पर भव्य माँ काली पूजा का आयोजन

8 से 10 नवंबर तक होंगे धार्मिक कार्यक्रम, समिति ने की व्यापक तैयारी



8 नवंबर (रविवार)
दोपहर 3 बजे : कलश स्थापना
शाम 4 बजे : शिव तांडव
शाम 5:30 बजे : चंडी पाठ
रात्रि 11 बजे : माँ काली की पूजा
रात्रि 2 बजे : देवी अभिषेक
प्रातः 3 बजे : दीपदान एवं बलिदान
प्रातः 4 बजे : पुष्पाललि
प्रातः 4:30 बजे : महाभोग, हवन व आरती

9 नवंबर (सोमवार)
शाम 7 बजे : महाआरती
कन्या पूजन व कन्याभोज
महाकाली भंडारा
माता को चुनरी भेंट
भगवती जागरण एवं गरबा महोत्सव

10 नवंबर (मंगलवार)
सिंदूर दान एवं
भव्य विसर्जन शोभायात्रा



17 साल से जारी मां काली की आराधना,सूरजपुर में तीन दिन गूजेगा भक्ति का उल्लास सूरजपुर में मां काली पूजा की भव्य तैयारी,8 से 10 नवंबर तक होंगे धार्मिक आयोजन

कलश स्थापना से विसर्जन शोभायात्रा तक,17 वें वार्षिकोत्सव को लेकर जुटी मां काली पूजा समिति

—संवाददाता—
सूरजपुर,27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

नगर में आस्था, भक्ति और धार्मिक परंपरा का प्रतीक बन चुके श्री श्री सार्वजनिक मां काली पूजा समिति के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं,समिति इस वर्ष अपना 17वां वार्षिकोत्सव मनाने जा रही है, इसके तहत भैयाथान रोड स्थित पंचमंदिर परा के दुर्गा बाड़ी परिसर में मां काली की पूजा-अर्चना के लिए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है,आयोजन को गरिमाय और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए रविवार को अग्रसेन भवन में समिति की बैठक आयोजित की गई,बैठक में पूजा-अर्चना के समय, धार्मिक अनुष्ठानों, महाभंडारा, भगवती जागरण,गरबा महोत्सव और विसर्जन शोभायात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई, साथ ही आयोजन के सुचारु संचालन

8 नवंबर को कलश स्थापना से शुरू होंगे धार्मिक अनुष्ठान...

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रविवार 8 नवंबर को दोपहर 3 बजे कलश स्थापना के साथ धार्मिक आयोजन की शुरुआत होगी,शाम 4 बजे शिव तांडव और साढ़े पांच बजे चंडी पाठ का आयोजन किया जाएगा,इसके बाद रात 11 बजे से मां काली की विशेष पूजा-अर्चना प्रारंभ होगी,रात 2 बजे देवी अभिषेक,सुबह 3 बजे दीपदान एवं बलिदान तथा सुबह 4 बजे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी,सुबह साढ़े चार बजे माता रानी को महाभोग लगाया जाएगा, इसके बाद हवन और आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे,पूजा के लिए पंडाल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है,समिति के सदस्य श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं।

के लिए समिति के पदाधिकारियों और अलग-अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई, समिति के सदस्यों के अनुसार, पिछले 17 वर्षों से सार्वजनिक रूप से मां काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है,इस दौरान नगर के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां काली की दर्शन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लगातार आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम अब

सूरजपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है।

9 नवंबर को कन्या पूजन, महाभंडारा और भगवती जागरण-सोमवार 9 नवंबर को शाम 7 बजे महाआरती के बाद कन्या पूजन एवं कन्याभोज का आयोजन होगा,इसके साथ ही महाकाली का भंडारा,माता को चुनरी भेंट करने का कार्यक्रम, भगवती जागरण और गरबा महोत्सव आयोजित किए

जाएंगे,आयोजन में महाभंडारा प्रमुख आकर्षण रहेगा। इसके लिए समिति ने अलग से जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को भोजन वितरण में किसी तरह की असुविधा न हो, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भक्ति संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बनाने की तैयारी है।

10 नवंबर को निकलेगी भव्य विसर्जन शोभायात्रा- मंगलवार 10 नवंबर को सिंदूरदान के बाद मां काली की भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी, तीन दिवसीय आयोजन का समापन धार्मिक परंपराओं के अनुरूप होगा,समिति की ओर से पूजा से लेकर विसर्जन तक की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की तैयारी की जा रही है।

आयोजन के संचालन के लिए समिति गठित- आयोजन के सुचारु संचालन के लिए समिति ने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं,इनमें रामकृष्ण ओझा, चंचलेश

श्रीवास्तव,मुकेश गर्ग और पवन मित्तल को संरक्षक बनाया गया है,रूपेश मित्तल अध्यक्ष, रामजी साहू,आशीष गुप्ता और संजीत गुप्ता उपाध्यक्ष,संजय गर्ग तथा कृष्णमंगल हरिओम अग्रवाल कोषाध्यक्ष, अजय सिंह और आशिक सोनी बाबू सचिव तथा प्रवीण साहू और विककी साहू सहसचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे, व्यवस्थापक के रूप में प्यारे साहू, सुमित मिश्र,रंजेश महाराज और नितेश गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है,पूजा प्रमुख विकास साहू और स्पर्श श्रीवास्तव बनाए गए हैं, 9 नवंबर को आयोजित होने वाले विशाल भंडारे के लिए रामबिलास मित्तल, पूनम गर्ग, दिनेश गुप्ता, सुंदरलाल पाटकर, निरंकर सिंह चौहान और भोला साहू को भंडारा प्रमुख बनाया गया है, समिति के सदस्यों में शंकर अग्रवाल, मनोज सोनी, रंजेश जायसवाल, रंजेश महाराज, मयंक तिवारी, अमन ठाकुर, संदीप ठाकुर, लाला साहू, शुभम अग्रवाल, मित गुप्ता, नवीन गुप्ता, वीरू गुप्ता, दीपक साहू, अद्वैत मित्तल,

अंशुल अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अंकुर तिवारी, ओमकार सोनी, महादेव साहू, रोहित सिंह, दीपक साहू,पिंटू, प्रवीण गोयल, गोलू पांडेय, कृष्णा गुप्ता, ऋषभ जैन, नितित सोनी, वंश अग्रवाल और काशवी मित्तल शामिल हैं।

बाल गणेश पूजा समिति भी तैयारियों में जुटी-आयोजन की तैयारियों में श्री श्री सार्वजनिक मां काली पूजा समिति के सदस्यों के साथ सहयोगी संस्था श्री बाल गणेश पूजा समिति के सदस्य भी सक्रिय हैं,दोनों समितियों के सदस्य पंडाल निर्माण,पूजा-अर्चना,भंडारा और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने में जुटे हैं, पिछले वर्षों की तरह इस बार भी आयोजन में नगर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, 17 वें वार्षिकोत्सव के माध्यम से समिति धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ नगर में सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक सहभागिता की परंपरा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का प्रदर्शन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

संयुक्त मंच के आह्वान पर मंगलवार को सरगुजा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर परिसर में नारेबाजी कर शासन से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लंबे समय से उनके अधिकार, मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे



लंबित हैं। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित करने की मांग की गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर सीधे पदोन्नति देने की मांग रखी गई। इसके अलावा समूह बीमा, पेंशन, ग्रेजुएट और भविष्य निधि (पीएफ) की

सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। संयुक्त मंच ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग भी उठाई। वहीं, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ताओं को पांच लाख और सहायिकाओं को तीन लाख रुपए की

राशि तत्काल देने की मांग की गई। पांचवीं मांग में मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष मानदेय में एक हजार रुपए की वृद्धि करने की बात कही गई।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी : संघ की प्रांताध्यक्ष कविता यादव ने कहा कि आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि कार्यकर्ता-सहायिकाओं के अधिकार और सम्मान की साझा लड़ाई है। उन्होंने शासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर समयबद्ध निर्णय लेने की अपील की। सरगुजा जिलाध्यक्ष अंजू सरकार ने कहा कि जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं अपने अधिकारों के लिए एकजुट हैं। जिला सचिव लीलावती राजवाड़े और जिला उपाध्यक्ष रानी यादव ने भी मांगों पर सरकार के तत्काल प्रतिक्रिया की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

भगवान परशुराम मंदिर परिसर में गरबा-डांडिया की धूम

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,27 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सर्व ब्राह्मण समाज की महिला विंग द्वारा अध्यक्ष माधुरी लता दुबे की अध्यक्षता में भगवान परशुराम मंदिर परिसर में गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज की महिलाएं रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर शामिल हुईं। संगीत और गरबा की धुन पर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद स्वरूप खीर का वितरण किया गया। महिलाओं ने आपसी मेल-मिलाप के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष माधुरी लता दुबे के साथ इति चतुर्वेदी, रेणुका उपाध्याय,सुधा तिवारी,शशिकला तिवारी,मिलन शर्मा, स्नेहलता दुबे,मांडवी शर्मा,अनीता शुक्ला,सुनीता व्यास,अनुपमा त्रिपाठी, नमिता पांडे, प्रेमलता पांडे,मुक्ति मिश्रा,नीतू तिवारी,सुनीता पांडे,माधुरी त्रिपाठी,संगीता तिवारी,मंजू तिवारी,अनुभा डबराल,मीना दुबे,शुभी दुबे, सौम्या दुबे,गीता दुबे,कफिका दुबे और वीना दुबे सहित अन्य महिलाओं का सहयोग रहा।



राम मंदिर के सामने 10 फीट ऊंची सड़क बनी मुसीबत,हादसे की आशंका

एनएच-343 निर्माण पर ग्रामीणों का आक्रोश,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन...

आनंद यादव

बलरामपुर,27 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के निर्माण कार्य को लेकर बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पस्ता में विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सार्वजनिक राम मंदिर के सामने सड़क का स्तर करीब 8 से 10 फीट तक ऊंचा कर दिया गया है। इससे मंदिर के आसपास आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क का लेवल सुधारने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार,राम मंदिर के पास पहले से सीसी सड़क बनी हुई है, जिससे लोगों का आवागमन सुचारु रूप से होता था। अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान सड़क की ऊंचाई बढ़ने से पुराने मार्ग और नई सड़क के बीच काफी अंतर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों को सड़क पर चढ़ाने-उतारने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के आसपास हाई स्कूल,गैस गोदाम और पावर हाउस की ओर जाने वाला मार्ग है। वहीं,पूर्व दिशा में शासकीय



अस्पताल और मुख्य बाजार रोड स्थित है। ऐसे में सड़क के स्तर में अधिक अंतर होने से विद्यार्थियों, मरीजों,बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ सकता है। उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान स्थानीय रास्तों और आसपास की बसाहट की जरूरतों को पर्याप्त ध्यान में नहीं रखा गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सड़क का लेवल निर्धारित करते समय पुराने संपर्क मार्गों,मंदिर परिसर और आसपास के आवागमन को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा का होगा अनावरण, सीएम व केन्द्रीय मंत्री होंगे शामिल कला केंद्र मैदान से निकलेगी नगर शोभायात्रा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जनजातीय समाज के महान शिक्षाविद् और समाज सुधारक पंथराज साहेब बाबा कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुरुवार को अम्बिकापुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक पदाधिकारी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति और नगर निगम ने तैयारियां की हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे कला केंद्र मैदान में जनजातीय समाज के लोगों के एकत्रीकरण के साथ होगी। सुबह 11 बजे यहां से नगर शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा गांधी चौक, घड़ी चौक,



संगम चौक, महामाया चौक, गुदरी चौक और जोड़ा पीपल चौक होते हुए बाबा कार्तिक उरांव चौक पहुंचेगी। यहां अतिथियों द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद शोभायात्रा पुनः कला केंद्र मैदान पहुंचेगी। प्रतिमा अनावरण के बाद कला केंद्र मैदान में मुख्य मंचीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें जनजातीय समाज की लोकसंस्कृति और पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। वक्ता बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष, शिक्षा, सामाजिक स्वाभिमान, सांस्कृतिक

अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों पर विचार रखेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चलेगा। समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री रामविचार नेताम, केंदार करयण, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े,रयाम बिहारी जायसवाल और राजेश अग्रवाल सहित सांसद चिंतामणि महाराज, अन्य जनप्रतिनिधि और जनजातीय समाज के पदाधिकारी शामिल होंगे। उक्त जानकारी बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति के महासचिव इन्दर भगत ने दी है।

बलरामपुर में बाइक चोर गिरफ्तार,बुलेट और होडा शाइन बरामद गैस गोदाम और जिला अस्पताल परिसर से चोरी हुई थीं दोनों मोटरसाइकिलें,आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

—संवाददाता—
बलरामपुर,27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले में मोटरसाइकिल चोरी की दो वारदातों का खुलासा करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार चोरी की गई रॉयल एनफील्ड बुलेट और होडा शाइन मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अम्बिकापुर भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चोरी की पहली घटना 12 सितंबर 2026 की रात की है। इडेन गैस



गोदाम बलरामपुर के पास से रॉयल एनफील्ड बुलेट चोरी हो गई थी। मामले में सिटी कोतवाली बलरामपुर में अपराध क्रमांक 161/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) में अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद 26 सितंबर की रात जिला अस्पताल बलरामपुर परिसर से होडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी होने की दूसरी घटना सामने आई।

इस मामले में अपराध क्रमांक 175/2026 के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों घटनाओं में अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही पुलिस को मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने सुशील शांडिल्य (26), पिता साधवन शांडिल्य, निवासी ग्राम धंधापुर, थाना राजपुर, वर्तमान पता नमनकला, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने दोनों मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की।

अधूरी सड़क और वन विभाग की फेंसिंग पर सवाल, अविनाश पाटक ने कलेक्टर को सौंपे दो झापन

कटगोड़ी-चरचा सड़क पूरी कराने की मांग, सोनहत-देवगढ़ फेंसिंग की जांच पर जोर, सड़क निर्माण से सरकारी कामों की गुणवत्ता तक, अविनाश पाटक ने उठाए दो जनहित के मुद्दे

—संवाददाता—

बैकुंठपुर, 27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिले में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और शासकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर दो महत्वपूर्ण मुद्दे प्रशासन के सामने उठाए गए हैं, संसद प्रतिनिधि एवं जिला कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश पाटक ने कलेक्टर कोरिया से मुलाकात कर दो अलग-अलग झापन सौंपे, पहले झापन में कटगोड़ी से चरचा तक अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग की गई, जबकि दूसरे झापन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत सोनहत एवं देवगढ़ रेंज में एएनआर योजना के तहत कराए गए तार फेंसिंग कार्यों की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई।

दोनों झापनों के जरिए एक ओर क्षेत्रीय आवागमन की समस्या के समाधान की आवश्यकता बताई गई, तो दूसरी ओर वन विभाग के निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों के पालन और सरकारी धन के उपयोग को लेकर सवाल खड़े किए गए, अविनाश पाटक ने प्रशासन से दोनों मामलों की गंभीरता से समीक्षा कर संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, कटगोड़ी-चरचा सड़क का मामला लंबे समय से अधूरे पड़े निर्माण कार्य और क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था से जुड़ा है, वहीं, सोनहत एवं देवगढ़ रेंज में तार फेंसिंग की स्थिति को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राकलन और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हुए हैं या नहीं।

पांच किलोमीटर की सीधी दूरी, लेकिन आवागमन में लगाना पड़ता है लंबा चक्कर

अविनाश पाटक ने कलेक्टर को सौंपे पहले झापन में कटगोड़ी से चरचा तक सड़क निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, उन्होंने बताया कि कटगोड़ी और चरचा कोयलांचल क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान हैं, दोनों के बीच सीधी दूरी लगभग पांच किलोमीटर बताई गई है, लेकिन वर्तमान आवागमन व्यवस्था के कारण लोगों को अपेक्षाकृत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, झापन में दावा किया गया है कि यदि प्रस्तावित सड़क का निर्माण पूरा हो जाता है, तो आवागमन की दूरी में लगभग 20 किलोमीटर तक की कमी आ सकती है, इससे क्षेत्र के लोगों को समय और परिवहन खर्च की बचत होने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहूलियत मिल सकती है, यह मार्ग क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क उपलब्ध होने से स्थानीय नगरों और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि, दूरी में संभावित कमी और सड़क की उपयोगिता का सटीक आकलन संबंधित विभाग के मार्ग नक्शे, वर्तमान सड़क मार्ग तथा प्रस्तावित सड़क की लंबाई के आधार पर आगे की कार्ययोजना स्पष्ट की जानी



करिव 20 किलोमीटर का चक्कर घटाने की मांग... वन विभाग के फेंसिंग कार्यों की जांच की अपील

स्टीमेट के अनुरूप काम हुआ या नहीं, जांच में हो स्पष्ट

सरकारी निर्माण कार्यों में स्वीकृत प्राकलन और तकनीकी मापदंडों का पालन महत्वपूर्ण होता है, इसी आधार पर अविनाश पाटक ने मांग की है कि एएनआर तार फेंसिंग के निर्माण की जांच संबंधित स्टीमेट और तकनीकी मानकों के अनुरूप कराई जाए, जांच के दौरान कार्य से जुड़े स्वीकृत प्राकलन, माप पुस्तिका, सामग्री के उपयोग और भूगतान संबंधी अभिलेखों की समीक्षा की जा सकती है, इसके साथ ही स्थल पर उपलब्ध निर्माण की स्थिति का मिलान विभागीय रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक कार्य और दस्तावेजों में दर्ज प्रगति के बीच किसी अंतर की स्थिति स्पष्ट हो सके, अविनाश पाटक ने यह भी मांग की है कि यदि जांच में अनियमितता या लापरवाही प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इस मामले में निष्पक्ष जांच का महत्व इसलिए भी है कि इससे आरोपों की तथ्यात्मक स्थिति सामने आ सकेगी, यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो संबंधित विभाग तथ्य प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट कर सकता है, वहीं, यदि कमियां प्रमाणित होती हैं, तो नियमों के अनुसार सुधार और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य बीच में क्यों बंद हुआ?

झापन के अनुसार, कटगोड़ी से चरचा तक सड़क निर्माण कार्य पूर्व में शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारणों से इसे बीच में ही रोक दिया गया, इसके बाद से मार्ग को पूरा करने की आवश्यकता बनी हुई है। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि निर्माण कार्य किस स्थिति में बंद हुआ, कितने हिस्से में काम पूरा हुआ और शेष निर्माण को पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, अविनाश पाटक ने मांग की है कि संबंधित विभाग सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करे और अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करे, यदि पूर्व में निर्माण के लिए स्वीकृति, बजट या तकनीकी प्रक्रिया पूरी की गई थी, तो उसके आधार पर आगे की कार्ययोजना स्पष्ट की जानी

चाहिए, किसी सड़क परियोजना का बीच में रुक जाना केवल निर्माण कार्य का मामला नहीं होता, बल्कि इससे उस मार्ग पर निर्भर लोगों की अपेक्षाएं भी प्रभावित होती हैं, ऐसे में परियोजना की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करना और निर्माण अधूरा रहने के कारणों की जानकारी सामने लाना जरूरी है।

कोयलांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने की मांग...

कटगोड़ी और चरचा के बीच सड़क निर्माण की मांग क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाई गई है, सड़क पूरी होने पर स्थानीय लोगों को आवागमन के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल सकता है, इससे समय की बचत के साथ परिवहन संबंधी खर्च कम होने की संभावना भी बताई गई है, अविनाश पाटक ने प्रशासन से इस मार्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य

वन क्षेत्र में फेंसिंग की उपयोगिता और गुणवत्ता दोनों महत्वपूर्ण

वन क्षेत्र में तार फेंसिंग जैसे निर्माण कार्यों का उद्देश्य निर्धारित क्षेत्र के घेराव और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होता है, ऐसे कार्यों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं और उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, यदि पोल और तार वास्तव में जगह-जगह गिर रहे हैं, जैसा कि झापन में आरोप लगाया गया है, तो इससे फेंसिंग की प्रभावशीलता प्रभावित होने की आशंका हो सकती है, हालांकि, इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए मौके पर निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण आवश्यक है, ऐसे मामलों में केवल शिकायत या विभागीय जवाब के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री, स्वीकृत लागत और वास्तविक स्थिति का संयुक्त परीक्षण किया जाना चाहिए, इससे सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की मांग की है, झापन की प्रतिलिपि भारत सरकार के कोयला मंत्री और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भी भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, ताकि संबंधित स्तर पर इस विषय पर ध्यान दिया जा सके, अब यह देखना होगा कि सड़क निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग क्या जानकारी उपलब्ध कराता है और अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की जाती है, निर्माण की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत राशि और शेष कार्य का विवरण सामने आने से इस मांग की प्रशासनिक स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।

सोनहत-देवगढ़ रेंज में एएनआर तार फेंसिंग की गुणवत्ता पर सवाल

दूसरे झापन में अविनाश पाटक ने कोरिया वनमंडल के अंतर्गत सोनहत और देवगढ़ रेंज में एएनआर योजना के तहत कराए गए तार फेंसिंग

कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया और कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद ही सीमेंट के पोल तथा तार जमीन पर गिरने लगे, झापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्माण के दौरान बालू और सीमेंट का निर्धारित अनुपात में उपयोग नहीं किया गया, यदि स्थल निरीक्षण और तकनीकी जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री के उपयोग और कार्य की निगरानी से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करना आवश्यक होगा, फिलहाल ये आरोप झापन के माध्यम से लगाए गए हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है, इसलिए निर्माण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभागीय अभिलेखों, स्वीकृत प्राकलन और तकनीकी मानकों के आधार पर निष्पक्ष जांच जरूरी होगी।

केवल कागजी जांच नहीं, मौके पर हो भौतिक सत्यापन

अविनाश पाटक ने मांग की है कि सोनहत और देवगढ़ रेंज में एएनआर योजना के अंतर्गत कराए गए तार फेंसिंग कार्यों की जांच केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित न रहे, जांच के दौरान संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर यह देखा जाना चाहिए कि सीमेंट पोल और तारों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निर्माण कार्य स्वीकृत प्राकलन के अनुरूप कराया गया है या नहीं, उन्होंने निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, पोल की मजबूती, तारों की स्थिति और कार्य की पूर्णता की जांच कराने की मांग की है, इसके साथ ही स्वीकृत राशि और वास्तविक निर्माण के बीच किसी अंतर की स्थिति में उसका कारण भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, यदि किसी स्थान पर पोल और तार गिरने की शिकायत है, तो उस स्थान का भौतिक सत्यापन कर निर्माण की मजबूती तथा संभावित तकनीकी खामियों का परीक्षण किया जा सकता है, इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि समस्या निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री, रखरखाव या किसी अन्य कारण से जुड़ी है।

दो झापन सौंपकर प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा

कलेक्टर कोरिया को सौंपे गए दोनों झापनों के माध्यम से अविनाश पाटक ने जिले से जुड़े दो अलग-अलग जनहित के मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, कटगोड़ी-चरचा सड़क का मामला क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बनाने और अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने से जुड़ा है, जबकि सोनहत एवं देवगढ़ रेंज में एएनआर तार फेंसिंग का मामला निर्माण की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं की जांच से संबंधित है, एक मामले में सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, दूसरे मामले में निर्माण की गुणवत्ता और स्वीकृत प्राकलन के अनुपालन की जांच की मांग की गई है, दोनों ही मामलों में संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रशासन इन झापनों पर क्या कार्रवाई करता है, सड़क निर्माण के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है और वन विभाग के फेंसिंग कार्यों की जांच कराई जाती है या नहीं, फिलहाल दोनों मुद्दों पर झापन के माध्यम से मांग उठाई गई है, सड़क निर्माण और फेंसिंग की गुणवत्ता को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित विभागों की जांच, अभिलेखों और आधिकारिक आर्वाइव के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सीएम हेलपलाइन की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : कलेक्टर यादव

समय-सीमा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, अपार आईडी का कार्य लंबित होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

—संवाददाता—

कोरिया, 27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्रीमती रश्मिका यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेलपलाइन में प्राप्त शिकायतों का समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही सेवा सेतु, जनदर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में समुचित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को 'सुध्वर छत्तीसगढ़' पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ किसान सम्मान निधि के पंजीयन कार्य को गंभीरता से पूरा करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने को कहा, ताकि प्रकरणों के निराकरण में विलंब न हो।



जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में पालकों को न हो अनावश्यक परेशानी

कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लेटलतपी पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी पालक को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी को इस कार्य को गंभीरता से कराने के निर्देश दिए गए। विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने एवं दर्ज करने का कार्य लंबित होने पर कलेक्टर ने जिला

शिक्षा अधिकारी से नाराजगी व्यक्त की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर विद्यार्थियों की पढ़ाई की स्थिति का जायजा लेने तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा।

'अप्रारंभ पीएम आवासों का निर्माण शुरू कराएं, अधूरे आवास जल्द करें पूर्ण'

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जनपद पंचायत बैकुंठपुर और सोनहत के मुख्य कार्यपालन

अधिकारियों से स्वीकृत आवासों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अप्रारंभ आवासों का निर्माण तत्काल शुरू कराने तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जनपद सीईओ को गांवों में जाकर निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने तथा हितग्राहियों, सरपंचों और पंचायत सचिवों से समन्वय स्थापित कर तहत जिले के अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर निर्माण में आ रही बाधाओं का निराकरण

कराने के निर्देश दिए।

नशे में वाहन चलाने और ओवरलोडिंग पर करें कार्रवाई

कलेक्टर श्रीमती यादव ने जिला परिवहन अधिकारी को बसों, ऑटो सहित यात्री वाहनों की नियमित जांच करने तथा क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाने वालों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। साथ ही तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए।

नल-जल योजना के अपूर्ण कार्य शीघ्र पूरे कराएं

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग की नल-जल योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिले के अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पेशान प्रकरणों की स्थिति की भी जानकारी ली।



58 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया खाना...

—संवाददाता—

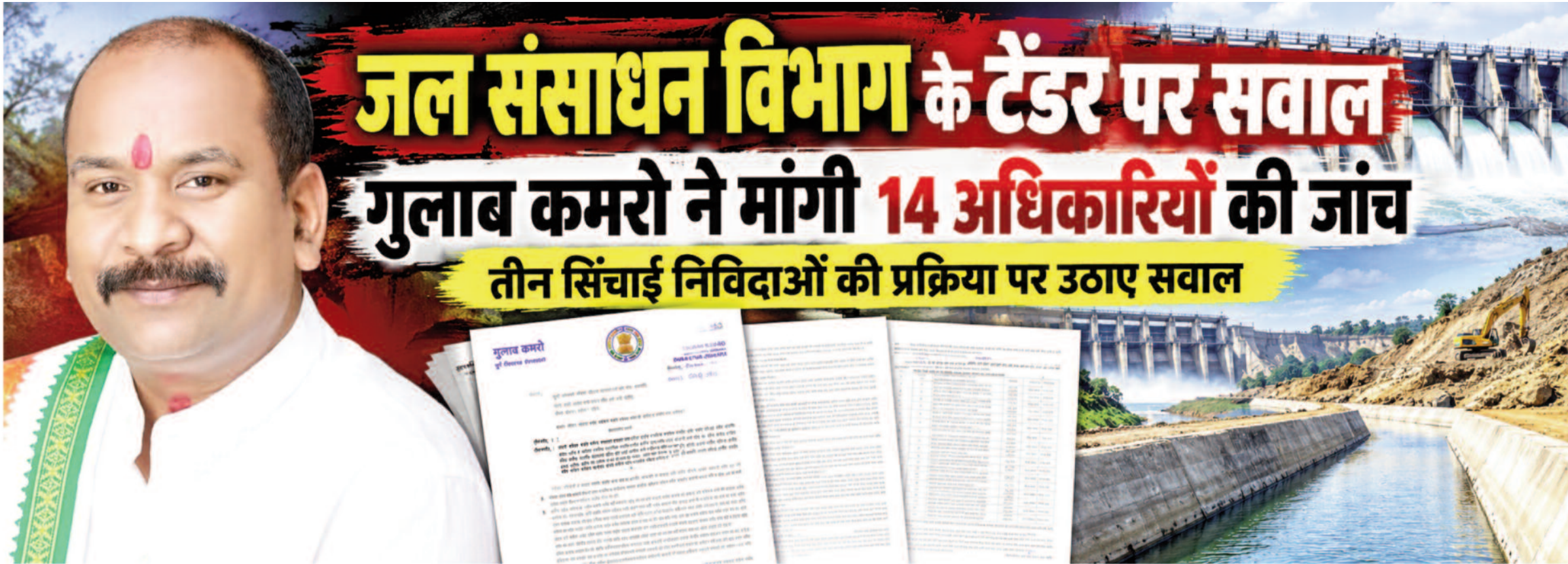
कोरिया, 27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

श्रीरामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम की यात्रा के लिए कोरिया जिले के 108 श्रद्धालुओं को मंगलवार को बैकुंठपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से खाना किया गया। इनमें 58 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, रायपुर के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं



जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में दर्शनार्थियों को बसों के माध्यम से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के लिए खाना किया गया। वहां से श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला

पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को खाना किया। इस अवसर पर योजना के नोडल अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के उप संचालक भी उपस्थित रहे।



5,576 करोड़ की 3 सिंचाई निविदाओं पर सवाल, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मांगी 14 अधिकारियों की जांच

तीन बड़े टेंडर, हजारों करोड़ की राशि और पात्रता पर सवाल! गुलाब कमरो ने खोला शिकायत का मोर्चा, 5,576 करोड़ की निविदाओं पर निरस्तीकरण की मांग... अपात्र फर्मों को पात्र बनाने का आरोप

सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर पर घमासान, 14 अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में लाने की मांग...
तीन निविदाओं में कथित गड़बड़ी का आरोप, गुलाब कमरो ने मुख्य सचिव से की शिकायत

जल संसाधन विभाग के बड़े टेंडरों पर सवालों की बौछार, जांच और निलंबन की मांग...
हजारों करोड़ के सिंचाई टेंडर पर उठे सवाल, पात्रता से लेकर अधिकारियों की भूमिका तक जांच की मांग...
5,576 करोड़ की निविदाओं पर शिकायत से हलचल, टेंडर रद्द कर दोबारा प्रक्रिया अपनाने की मांग...

-रवि सिंह-

रायपुर/एमसीबी, 27 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने गंभीर सवाल उठाए हैं, उन्होंने इस संबंध में राज्य शासन के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव को शिकायत भेजकर लगभग 5,576 करोड़ रुपये की कुल निविदा राशि से जुड़ी तीन निविदाओं को निरस्त करने, पारदर्शी प्रक्रिया से दोबारा आमंत्रित करने तथा कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कराने की मांग की है। गुलाब कमरो की शिकायत में निविदा क्रमांक 190885, 190886 और 190888 का उल्लेख है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि तकनीकी मूल्यांकन और दर खोलने की प्रक्रिया में पात्रता संबंधी गंभीर विसंगतियां सामने आने के बावजूद कुछ ठेकेदारों को पात्र माना गया, उन्होंने आरोपों के समर्थन में निविदावार विवरण देते हुए संबंधित अधिकारियों की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया है,

शिकायत के तीसरे पृष्ठ पर 14 अधिकारियों के नाम, पद और उनकी बताई गई भूमिका की सूची संलग्न है, हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, इन मामलों में विभागीय जांच, मूल निविदा अभिलेखों और तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

तीन निविदाएं, हजारों करोड़ की राशि और पात्रता पर सवाल...

शिकायत के अनुसार, तीनों निविदाएं अलग-अलग सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित हैं, इनमें सिकासार-कोडार रिजर्वायर लिंक कैनाल, मोहामेला-सिसरार बैराज तथा मटनार-देवसराय बैराज परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता ने निविदाओं की पात्रता प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि अपात्र फर्मों को नियमों के विपरीत पात्र घोषित किया गया है, तो इससे प्रतिस्पर्धा और सरकारी धन के उचित उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, शिकायत में निविदा राशि लगभग 5,576 करोड़ रुपये बताई गई है, इसके साथ ही जीएसटी सहित लगभग 4,760 करोड़ रुपये की राशि का भी उल्लेख किया गया है, इन दोनों आंकड़ों का सटीक वित्तीय मिलान संबंधित निविदा दस्तावेजों और विभागीय रिकॉर्ड से किया जाना आवश्यक है, कमरो ने शासन से अग्रह किया है कि केवल शिकायत के आधार पर औपचारिक जवाब लेकर मामला समाप्त न किया जाए, बल्कि निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जांच की जाए, इसमें निविदा शर्तों, तकनीकी पात्रता, अनुभव प्रमाणपत्र, उपलब्ध कार्यभार, वित्तीय क्षमता और मूल्यांकन से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण शामिल होना चाहिए।

पहली निविदा में एनसीसी और रिथविक प्रोजेक्ट्स की पात्रता पर आपत्ति

शिकायत में निविदा क्रमांक 190888, मटनार-देवसराय बैराज परियोजना का उल्लेख किया गया है, इसकी अनुमानित लागत लगभग 1,636.69 करोड़ रुपये बताई गई है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एल-1 के रूप में उल्लेखित एनसीसी लिमिटेड के पास निविदा में मांगी गई भौतिक क्षमता संबंधी योग्यता उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उसे पात्र मानकर आगे बढ़ाया गया, इसी निविदा में रिथविक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की पात्रता पर भी आपत्ति जताई गई है, शिकायत के मुताबिक, संबंधित कंपनी के अन्य कार्यों और उपलब्ध कार्यभार के दस्तावेजों की तुलना करने पर उसकी पात्रता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि निविदा प्रक्रिया में कार्यभार

शिकायत में नामजद अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	शिकायत में उल्लिखित पद
1	जितेंद्र नेताम	प्रमुख अभियंता
2	आवताब आलम	मुख्य अभियंता, निविदा प्रकोष्ठ
3	संजय गुप्ता	कार्यपालन अभियंता, निविदा प्रकोष्ठ
4	अरविंद कोसल	कार्यपालन अभियंता, निविदा प्रकोष्ठ
5	अनन्या गुप्ता	कार्यपालन अभियंता, निविदा प्रकोष्ठ
6	आई.ई. सिद्धकी	अधीक्षण अभियंता, गरियाबंद
7	एस.के. बर्मन	कार्यपालन अभियंता, गरियाबंद
8	मकसी कुंजूर	मुख्य अभियंता/ विशेष कर्तव्य अधिकारी
9	एलेक्जेंडर ग्राहम	मुख्य अभियंता, जगदलपुर
10	नरेन्द्र कुमार पाण्डेय	अधीक्षण अभियंता, जगदलपुर
11	वेद प्रकाश पाण्डेय	कार्यपालन अइयंता, जगदलपुर
12	सुमन कुमार मिंज	मुख्य अभियंता, रायपुर
13	संतोष साहू	अधीक्षण अभियंता, रायपुर
14	ललित राजते	कार्यपालन अभियंता, रायपुर

और वित्तीय क्षमता से जुड़े तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया, इन आरोपों की पुष्टि के लिए कंपनी के प्रस्तुत दस्तावेजों, विभागीय मूल्यांकन रिपोर्ट और निविदा की मूल शर्तों का परीक्षण आवश्यक होगा, संबंधित कंपनियों और विभाग का पक्ष सामने आने के बाद ही इस मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

मोहामेला-सिसरार बैराज निविदा पर भी सवाल...

शिकायत में निविदा क्रमांक 190886, मोहामेला-सिसरार बैराज परियोजना का भी उल्लेख किया गया है, इसकी लागत लगभग 574.73 करोड़ रुपये बताई गई है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस निविदा में संबंधित ठेकेदारों की कार्यक्षमता और पात्रता का आकलन करते समय आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया गया, शिकायत में ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड तथा सहायक निविदाकार एमएस दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का नाम दर्ज है, शिकायत के अनुसार, एक ओर कार्यभार पूरा नहीं होने और दूसरी ओर प्रस्तुत दस्तावेजों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए गए हैं, शिकायतकर्ता ने इन बिंदुओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत में आरोप दर्ज होना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, संबंधित अभिलेखों की जांच और विभागीय जवाब के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

सिकासार-कोडार परियोजना में अनुभव प्रमाणपत्र पर आपत्ति

तीसरी निविदा क्रमांक 190885 सिकासार-कोडार रिजर्वायर लिंक कैनाल, गरियाबंद से संबंधित है, शिकायत में इसकी अनुमानित लागत लगभग 2,549.86 करोड़ रुपये बताई गई है, इस निविदा में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की पात्रता पर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समान प्रकृति के कार्य का स्वतंत्र रूप से पूर्ण अनुभव होने संबंधी शर्तों का उचित परीक्षण नहीं किया गया, शिकायत में प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र और कार्य के वास्तविक हिस्से के बीच अंतर होने का दावा किया गया है, शिकायतकर्ता ने मांग की है कि अनुभव प्रमाणपत्रों, पूर्ण कार्यों की प्रकृति, वास्तविक निष्पादन और निविदा की पात्रता शर्तों का तकनीकी स्तर पर परीक्षण कराया जाए, यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

शिकायत के तीसरे पृष्ठ पर 14 अधिकारियों के नाम

इस प्रकरण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायत केवल निविदा प्रक्रिया पर सामान्य सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, तीसरे पृष्ठ पर संलग्न सूची में 14 अधिकारियों के नाम, पद और शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई कथित भूमिका का उल्लेख किया गया है, सूची में जितेंद्र नेताम, आवताब आलम, संजय गुप्ता, अरविंद कोसल, अनन्या गुप्ता, आई.ई. सिद्धकी, एस.के. बर्मन, मकसी कुंजूर, एलेक्जेंडर ग्राहम, नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, वेद प्रकाश पाण्डेय, सुमन कुमार मिंज, संतोष साहू और ललित राजते के नाम दर्ज हैं, शिकायत में अलग-अलग अधिकारियों की भूमिका निविदा पात्रता, नोटशीट तैयार करने, दस्तावेजों की स्वीकृति अथवा परिवर्तन और तकनीकी मूल्यांकन से संबंधित बताई गई है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपात्र फर्मों को पात्र घोषित करने की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए, यह सूची शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा है। इसे अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, संबंधित अधिकारियों का पक्ष उनकी वास्तविक भूमिका और विभागीय रिकॉर्ड की जांच इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।

टेंडर निरस्त करने और दोबारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग

गुलाब कमरो ने अपनी शिकायत में तीनों निविदाओं को तत्काल निरस्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा आमंत्रित करने की मांग की है, उन्होंने यह भी अग्रह किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित निविदाओं में अनुबंध या कायदेशि जारी करने से जुड़े कदमों की समीक्षा की जाए, इसके अलावा, शिकायत में सभी निविदाकारों के कार्यभार, बिड कैपेंसिटी, वित्तीय दस्तावेजों और अनुभव प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र सत्यापन कराने की मांग की गई है, शिकायतकर्ता ने अपात्र फर्मों को पात्र घोषित करने के लिए जिम्मेदार बताए गए अधिकारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच तथा निष्कर्षों के आधार पर निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है, शिकायत की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, प्रमुख सचिव और जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता सहित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को भी भेजे जाने का उल्लेख है।

अब शासन और विभाग के जवाब पर निगाहें...

तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की निविदाओं को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन और जल संसाधन विभाग शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या निविदाओं के मूल दस्तावेजों का स्वतंत्र परीक्षण कराया जाएगा? क्या तकनीकी पात्रता और अनुभव प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन होगा? और क्या शिकायत में नामजद अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाएगी? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही सामने आ सकता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं, तो जिम्मेदारी तय करना और नियमानुसार कार्रवाई करना आवश्यक होगा, वहीं, यदि जांच में आरोप पुष्ट नहीं होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और कंपनियों की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए, निष्कल यह मामला शिकायत में लगाए गए आरोपों और जांच की मांग से जुड़ा है, जल संसाधन विभाग, संबंधित अधिकारियों और निविदाकार कंपनियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर खबर को अद्यतन किया जाना चाहिए।

वोट रक्षक और चारपाई चौपाल से गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी कांग्रेस

दिल्ली की महारैली में सूरजपुर से 300 से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा

-संवाददाता-

सूरजपुर, 27 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच, पात्र नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना अभियान तेज करने की घोषणा की है, वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत पार्टी अब जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों और मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, इसके लिए 'वोट रक्षक' और 'चारपाई चौपाल' को अभियान का प्रमुख माध्यम बनाया जाएगा, कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपने निर्णयों को सार्वजनिक करने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के

वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत सूरजपुर में पत्रकार वार्ता, मतदाता सूची की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही पर उठाए सवाल

पर्यवेक्षक डॉ. देवाशीष पटनायक एवं छत्तीसगढ़ सहप्रभारी जरिता लैतप्रांग ने सूरजपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए, नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित रहना चाहिए, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है, कांग्रेस का कहना है कि चुनावी व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्णयों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आवश्यक है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बृथ स्तर तक नजर

पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई, उन्होंने कहा कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, तो ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें सामने लाया जाएगा, इसके लिए बृथ स्तर पर मतदाता सूचियों का



तीन चरणों में गांव-गांव तक पहुंचेगा अभियान

कांग्रेस ने अभियान को तीन चरणों में आगे बढ़ाने की रूपरेखा बताई, पहले चरण में जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता के माध्यम मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, दूसरे चरण में कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा, तीसरे चरण में बृथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर रणनीति तैयार कर पंचायतों तथा गांवों तक अभियान पहुंचाया जाएगा, इसी रणनीति के तहत 'वोट

रक्षक' और 'चारपाई चौपाल' के माध्यम से ग्रामीणों के बीच संवाद किया जाएगा, कांग्रेस का दावा है कि इस पहल से गांवों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जांचने, नाम कटने की जानकारी जुटाने और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता के वोट की रक्षा करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

दिल्ली की महारैली में सूरजपुर से जाएंगे 300 से अधिक कार्यकर्ता

जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत आयोजित महारैली में सूरजपुर जिले से लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अलग-अलग माध्यमों से दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस के देशव्यापी अभियान का हिस्सा बनेंगे, शशि सिंह के अनुसार, अपने वोट, संविधान और भविष्य की रक्षा के संकल्प के साथ जिले के ग्रामीणों के बीच संवाद किया जाएगा, कांग्रेस का दावा है कि इस पहल से गांवों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जांचने, नाम कटने की जानकारी जुटाने और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता के वोट की रक्षा करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

ईस्माइल खान, भगवती राजवाड़े, कुसुमलता राजवाड़े, नवीन जायसवाल, विद्यासागर सिंह, संजीव श्रीवास्तव, रमेश दनोदिया, अंशुल गोयल, चंदन सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, पंकज तिवारी, मेही साहू, परमेश्वर राजवाड़े, लिली राजवाड़े, जरीन सुल्ताना, होंगे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अलग-अलग माध्यमों से दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस के देशव्यापी अभियान का हिस्सा बनेंगे, शशि सिंह के अनुसार, अपने वोट, संविधान और भविष्य की रक्षा के संकल्प के साथ जिले के ग्रामीणों के बीच संवाद किया जाएगा, कांग्रेस का दावा है कि इस पहल से गांवों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जांचने, नाम कटने की जानकारी जुटाने और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता के वोट की रक्षा करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले...

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी,सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज,अधोसंरचना मिशन के लिए 500 करोड़ मंजूर...

रायपुर,27 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों,सरकारी कर्मचारियों, सड़क निर्माण,पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और खेल समेत कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के लिए पांच साल में 500 करोड़ का प्रावधान करने को मंजूरी दी। बैठक में पर्यटन विकास मिशन,खेल उत्कर्ष मिशन, औद्योगिक निवेश और कृषक उन्नति योजना में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

15 नवंबर से होगी धान खरीदी, 3100 प्रति किंवटल मिलेगा भाव

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होगी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति किंवटल की दर से अधिकतम 21 किंवटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। धान विक्रय के लिए एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को अलग से दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान बेचने के लिए ऋण पुस्तिका भी समिति में अलग से ले जाने की जरूरत नहीं होगी। धान के रकबे का निर्धारण डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित व्यवस्था अपनाई जाएगी। किसानों को धान बेचने में सुविधा देने के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। कैबिनेट ने समितियों में खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 में



एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में राहत जारी...

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अग्रे 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है। इस फैसले से लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना के तहत रियायत का लाभ मिलता रहेगा।

सड़क निर्माण के ठेकेदारों को डमर की बढ़ी कीमतों से राहत...

बिटुमिन यानी डमर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए कैबिनेट ने सड़क निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव से जुड़े ठेकेदारों को मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक ठेकेदारों द्वारा वास्तव में खरीदी और उपयोग की गई बिटुमिन की मात्रा पर राज्य सरकार बजट से 130.88 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। वहीं,लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य वित्तपोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव के उन अनुबंधों में भी राहत दी जाएगी, जिनकी निविदाएं 1 अप्रैल 2026 से पहले प्राप्त हुई थीं। इन कार्यों में 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक खरीदे और इस्तेमाल किए गए बिटुमिन पर मूल्य राहत दी जाएगी। इस पर लगभग 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। इस निर्णय से लंबित डमर सड़क निर्माण कार्यों को गति देने और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अतिशेष धान का नीलामी के माध्यम से निराकरण करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा कैशलेस इलाज : मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र कर्मचारियों और उनके

आश्रितों को कैशलेस उपचार मिलेगा। उन्हें इलाज के समय चिकित्सा खर्च का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। चिकित्सा सुविधा के लिए पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन तथा डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस व्यवस्था से गंभीर बीमारी और आपातकाल की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर उपचार मिलने के साथ आर्थिक राहत भी मिलेगी।



मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी,पांच साल में 500 करोड़ का प्रस्ताव

प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी गई है। 'पर्यटन से समृद्धि' के उद्देश्य के साथ यह मिशन अगले पांच वर्षों तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही होमस्टे,निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ प्रकरण वापस लेने की कार्रवाई...

मंत्रिपरिषद ने विद्युद् रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुमति दी है। यह निर्णय 30 सितंबर 2026 को हुई उपसमिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार लिया गया है।

नगर पंचायत कूय का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने की मंजूरी...

कैबिनेट ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कुंय का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कुंवरगढ़ को छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल बताया गया है। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों,ऐतिहासिक घरीरों और तालाबों के लिए जाना जाता है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से नगर पंचायत को उसकी ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप कुंवरगढ़ नाम देने की मांग कर रहे थे। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी,पांच साल में 500 करोड़ का प्रावधान : प्रदेश में अधोसंरचना विकास की योजना,परियोजना तैयारी,निर्माण गुणवत्ता, निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यह मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा। इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रस्तावित है, यानी हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। लोक निर्माण विभाग मिशन का नोडल विभाग होगा, जबकि छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी। मिशन के तहत प्रदेश के सड़क नेटवर्क का मास्टर प्लान तैयार करने,अधोसंरचना की जरूरतों का डेटा आधारित आकलन करने और परियोजनाओं के सर्वेक्षण व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले से तैयार करने पर ध्यान दिया

जाएगा। कार्यों के डिजिटलीकरण के लिए WAMIS और ई-माप पुस्तिका तथा समेकित नियोजन के लिए GIS आधारित व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा ऑडिट, सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा नए वित्तीय मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने, निर्माण में देरी और लागत बढ़ने की समस्या कम करने तथा कार्यों की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना है। मिशन के क्रियान्वयन से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के विशाल कोयला भंडार का मूल्यवर्धित उपयोग बढ़ाना और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना है।

295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी

कैबिनेट ने कटघोरा-तखलगुर-मुंगेली-कवार्थ-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शल-प्रतिशत इविटी निवेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस रेल परियोजना की लंबाई 295 किलोमीटर और अनुमानित लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपये है। परियोजना में कुल लागत के 25 प्रतिशत यानी करीब 2,000 करोड़ रुपये की अंशपूजी प्रस्तावित है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय लगभग 1,000-1,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। राज्य सरकार की हिस्सेदारी मिनरल डेवलपमेंट फंड,जिला खनिज न्याय और राज्य बजट के माध्यम से वहन की जाएगी। परियोजना से रेल सुविधा से वृद्धि क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही उद्योग, पर्यटन, रोजगार और कृषि उद्ये के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में तूफान अर्नब का असर,4 जिलों में रेड अलर्ट 90 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी,बस्तर के स्कूलों में छुट्टी

रायपुर,27 अक्टूबर 2026। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान अर्नब के बुधवार को ओडिशा-आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 60 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ जगहों पर 200 मिमी तक बारिश होने की संभावना है। 28 अक्टूबर के लिए चार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, रायपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात 'अर्नब' के असर को देखते हुए बस्तर के स्कूलों में कल छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए मौसम आधारित सलाह जारी की है। किसानों को अगले 2 से 4 दिन धान और अन्य फसलों की कटाई रोकने, कटी फसल को सुरक्षित रखने और खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में प्रदेश के



अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। **रायपुर में भी बदलेगा मौसम, दिन में 31 डिग्री तक रहेगा तापमान :** रायपुर में बादलों छाप रह सकते हैं। बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक था।

5 बैगा बच्चों की मौत...कांग्रेस नेता दीपक बैज और विक्रांत भूरिया ने सरकार को घेरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल



कवर्धा,27 अक्टूबर 2026। कबीरधाम जिले के नंदनी कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला लगातार तुल पकड़ रहा है। कांग्रेस नेता ममले को लेकर सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। चार दिन पहले कांग्रेस की सात सदस्यीय जांच टीम के बाद आज आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों और ग्रामियों से मुलाकात कर गांव की स्थिति जानी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन,कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आदिवासी बैगा परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। गांव में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति गंभीर है। वहीं पांच बच्चों की मौत के मामले में भी लापरवाही की आशंका को गंभीरता से जांचने की जरूरत है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच,जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। अब सवाल यह है कि पांच बच्चों की मौत के मामले में जांच कब पूरी होगी,जिम्मेदारी किसकी तय होगी और आदिवासी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

मंत्रालय घेरने निकले किसानों को पुलिस ने रोका...गोबर खाद को बढ़ावा देने,बकाया भुगतान समेत 10 मांगें,खदानों का भी विरोध

रायपुर,27 अक्टूबर 2026। रायपुर के तूता धरना स्थल पर मंगलवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मंत्रालय का घेराव करने निकले सैकड़ों किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद किसानों ने ज़ापन सौंपा और वापस लौट गए। किसानों ने खदानों का भी विरोध किया। उनकी 10 मांगों में केमिकल खाद की जगह गोबरधन खाद को बढ़ावा देना भी शामिल है। किसान धान बोसस,समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, बकाया भुगतान और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी मांगों को लेकर जुटे थे। किसानों ने साल 2022-23 की धान खरीदी का बकाया 1700 करोड़ रुपए तत्काल देने की मांग की है। किसानों ने संबंधित अधिकारी के नाम पुलिस को ज़ापन सौंपा। अपनी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद किसान लौट गए।

किसानों को मंत्रालय घेराव से रोका

मंत्रालय का घेराव करने निकले किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। हालांकि कुछ देर तक किसान वहीं अड़े रहे। भारतीय किसान संघ के धमतरी जिला अध्यक्ष लालाराम चंद्राकर ने कहा कि सरकार की घोषणा के बाद भी किसानों को पूरा भुगतान नहीं मिला है। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई समर्थन मूल्य की राशि भी किसानों को दी जानी चाहिए।



अधिकारी नहीं आए,तो घेराव करने से रोका...

कुरुद से आए किसान राज कुमार सिंह ने कहा, 'अधिकारी नहीं आए, तो हमें प्रदर्शन करने से रोका गया। हमें अपना रास्ता तय करने देना चाहिए। हमारी मांगों को भी तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।'

दूना पत्थर की खदान के खिलाफ भी विरोध...

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले से पहुंची महिला किसान लुकेशरी जंघेल ने कहा कि वे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उनके क्षेत्र में दूना पत्थर की खदान के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान नवीन शेष ने कहा कि किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धान खरीदी के दौरान टोकन को लेकर भी परेशानी होती है। वहीं,गायों के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिला किसान ने कहा, 'सरकार सड़क बनाने के नाम पर नहर तोड़ देती है। हम यह मनमानी नहीं चलने देंगे।'

नया रायपुर के प्रभावित किसान भी शामिल...

भारतीय किसान संघ के आंदोलन को नया रायपुर के प्रभावित किसानों ने भी समर्थन दिया। किसान नेता रूपन चंद्राकर ने बताया कि संघ ने उन्हें आशवासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने नया रायपुर से जुड़ी समस्याओं और मुआवजे के मुद्दे पर भी संघ से बात की।

विकास योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें विभागोंय उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रमों का मुख्य थीम 'सुसंस्कृत नारी, युवा उड़ान' निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों में शालीनता और गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी कार्यक्रमों में लाभाभित किया जाएगा।

1 से 3 नवंबर तक रोशन होंगे शासकीय भवन

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने बजट से आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि मुख्य अतिथियों के परामर्श से कार्यक्रमों का निर्धारण करते हुए आयोजन की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमाययी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सुकमा में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा माहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सांसद लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी। मुंगेली में विधायक पुनूलाल मोहले,धमतरी में विधायक अजय चन्द्राकर,मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

में विधायक रेणुका सिंह, गौस्ता-पेण्डु-मरवाही में विधायक अमर अग्रवाल,कोण्डगांव में विधायक सुशीला लता उरुई, नारायणपुर में विधायक विक्रम उरुई तथा बस्तर में विधायक किरण देव मुख्य अतिथि होंगे।

रायपुर में कारोबारी नितिन डागा के घर ईडी रेड...खुद को भूपेश बघेल का भतीजा बताकर ठगी करने वाले के यहां भी दबिश,जांच जारी

रायपुर,27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की। यह कार्रवाई रायपुर के पंडरी इलाके के रवि नगर स्थित सुशील विला में हुई। सुबह कारोबारी नितिन डागा के घर दो गाड़ियों में पहुंची टीम ने कई डॉक्यूमेंट्स की जांच की। इसके अलावा दुर्ग की ऋषभ कॉलोनी में बघेलस कॉर्पोरेट के फाउंडर और उगी के आरोपी गुलशन बघेल के घर ईडी की टीम ने दबिश दी। टीम दो गाड़ियों में पहुंची, जिसमें 10 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में होने की आशंका है। हालांकि,आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गुलशन बघेल, लक्ष्मी कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं। कंपनी बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण,अर्थवर्क,मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े काम करती है। कंपनी सरकारी और निजी क्षेत्र की निर्माण परियोजनाओं में भी काम करती है। करीब 6 साल पहले गुलशन बघेल पर खुद को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भतीजा बताकर सरकारी नौकरी लगवाने का दावा करने और एक महिला से उगी करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। रायपुर के पंडरी स्थित रवि नगर में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे ईडी ने नितिन डागा के घर छापेमारी की। दो गाड़ियों में पहुंचे आधा दर्जन अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। नितिन डागा का ज्वेलरी और जमीन का कारोबार बताया जा रहा है। फिलहाल ईडी की यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है,इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जांच का दायरा और कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण भी स्पष्ट नहीं हैं। मामले में आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।